व्यक्ति आय लगभग 300 डालर रही और 40 प्रतिशत से सभी अधिक भारतीय गरीबी रेखा से नीचे रहे ।

न केवल भारत की केन्द्रीयकृत आयोजना बल्कि 1950 के बाद विश्व बैंक की ऋण देने की नीतियों की भी आलोचना करते हुए प्रो० कामथ ने लिखा कि विश्व बैंक की भारत, तंजानिया, इथीयोपिया और मेक्सिको जैसे देशों में राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों की प्राथमिकताओं के कारण वह निराशाजनक स्थिति आई ।

प्रो० कामथ टिप्पणी करते हैं, भारत ने सर्वाधिक विश्व बैंक सहायता प्राप्त की— 1951 से 1989 तक 20 बिलियन डालर से भी अधिक, जिसका अधिकतर भाग सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं को मिला ।

विदेशी सहायता प्राप्त करने की एक पूर्व शर्त के रूप में सरकारों द्वारा व्यापक विकास योजना आरंभ करवाते हुए दाता राष्ट्रों और विश्व वित्तीय एजेंसियों ने विकासशील देशों के समाजीकरण को सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया, लेखक का यह निष्कर्ष था ।

श्री कामथ के अनुसार अमरीकी सहायता ने सरकारी उपक्रमों की जिम्मेवारी ली, अमरीकी सहायता का एक बड़ा भाग 1955 से 1971 तक दिया गया और 1951 से 1985 तक 5 प्रतिशत से भी कम निजी क्षेत्रों को दिया गया ।

उनकी टिप्पणी थी कि वाशिंगटन सहायता से सरकारी उर्वरक और औद्योगिक संयंत्रों, बड़ी सिंचाई परियोजनाओं, सरकार के स्वामित्व वाली विद्युत परियोजनाओं, राजमार्गों का निर्माण, सरकारी रेलवे प्रणाली के लिए लोकोमोटिव और रोलिंग स्टाक, को वित्त पोषित किया गया और एक महत्वपूर्ण भाग था खाद्य सहायता ।

उन्होंने स्वीकार किया कि सहायता की कथित सफलता के कुछ मामले रहे थे जैसे 1950 के दशक के आरंभ में और फिर दुबारा 1960 के दशक के मध्य में लाखों लोगों के भुखमरी के कगार पर होने पर महत्वपूर्ण खाद्य सहायता ।

उन्होंने कहा, अन्यथा, भारत को दी गई सहायता कम त्रासदी नहीं थी । यदि निजी क्षेत्र की कीमत पर सार्वजनिक क्षेत्र की वृद्धि को जाती है तो विदेशी सहायता विकास अर्थव्यवस्था के पुराने और झूठे सिद्धांत, कि आर्थिक विकास के लिए केवल पूंजी और प्रौद्योगिकी तक अभिगम्यता की आवश्यकता होती है, पर आधारित रही थी और अब भी जारी है ।

वे कहते हैं, आवश्यकता है केन्द्रीय योजना प्रणाली को खत्म करने की, अकुशल सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े पैमाने पर निजीकरण को, विदेशी व्यापार और बाहरी क्षेत्र के नियंत्रण को पूरी तरह से खत्म करना, निजी पूंजी और स्वैच्छिक एक्सचेंज तक पूर्ण अधिकार का नियमन और बहाली ।

Meaning of rationalisation of labour

1847. SHRI SOM PAL:
SHRI SARADA MOHANTY:
SHRIMATI MIRA DAS:
SHRI CHIMANBHAI MEHTA:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 79 given in the Rajya Sabha on 13th July, 1992 and state the meaning of rationalisation of labour, and what is the number of surplus staff in National Textiles Corporation mills and its percentage to total strength?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): Rationalisation of labour would mean optimisation of manpower to maximise productivity and efficiency within the parameters of technical feasibility and economic viability. 7,116 out of 14,952 or about 52 per cent of the officers and staff of NTC would be rendered surplus if the Turnaround strategy proposed by NTC were to be implemented.